गोलन हाइट्स पर राजनीति

लेखक -अरुण के. सिंह (पूर्व भारतीय राजदूत, अमेरिका और इजराइल में)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध) | द हिन्दू | 9 अप्रैल, 2019

"इजराइल की संप्रभुता को अमेरिका द्वारा दी गई मान्यता, नियमों पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए एक चुनौती है।"

21 मार्च को, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने लंबे समय से चली आ रही अमेरिकी नीति को उलटते हुए ट्वीट किया कि "52 वर्षों के बाद अब समय आ गया है, जब अमेरिका गोलन हाइट्स क्षेत्र पर इजराइल के प्रभुत्व को मान्यता दे, जो इजराइल और क्षेत्र की स्थिरता के लिए रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।"

तीसरा इजराइल समर्थक (प्रो-इजराइल) कदम

यह एक और प्रमुख इजराइल समर्थक कदम है, जिसे ट्रम्प ने राष्ट्रपति के रूप में लिया है। 8 मई, 2018 को, ट्रम्प ने ईरान के साथ 2015 में हुए जेसीपीओए (संयुक्त व्यापक योजना) समझौते से बाहर निकलना ज्यादा बेहतर समझा, जिसे 2015 में बराक ओबामा के अमेरिकी राष्ट्रपति रहने के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान ने परमाणु समझौता किया था। इजराइल ने ईरान के साथ समझौते और किसी भी प्रतिबंध पर राहत देने का विरोध किया था, सीरिया में ईरान की बढ़ती उपस्थिति से खुद को होने वाले नुकसान को देखते हुए और ईरान का लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास को दिए जा रहे समर्थन के कारण, इजराइल ईरान के अस्तित्व और उसकी सैन्य क्षमताओं को मान्यता देने से इनकार करता रहा है।

इससे पहले, 6 दिसंबर, 2017 को, व्हाइट हाउस के एक भाषण में, श्री ट्रम्प ने घोषणा की थी कि "मैंने निर्धारित किया है कि यह आधिकारिक तौर पर यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देने का समय आ गया है।" साथ ही ट्रम्प ने फिलिस्तीनी कार्यालय को बंद करने के लिए भी कदम बढ़ाये।

अब तक अमेरिकी नीति यह थी कि वास्तविक स्थिति, 1967 के इजराइल-अरब संघर्ष में इजराइल की जीत के बाद, में किसी भी तरह के बदलाव की औपचारिकता केवल संबंधित पक्षों के बीच बातचीत से ही हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSCR) के प्रस्ताव 242 (1967) और 338 (1973) में बल द्वारा किसी क्षेत्र का अधिग्रहण अमान्य था और इजराइली को वापस आने के लिए कहा गया था। UNSCR 497 (1981) के अनुसार, 'सीरियाई गोलन हाइट्स में अपने कानूनों, अधिकार क्षेत्र और प्रशासन को लागू करने का इजराइल का निर्णय अमान्य है।'

श्री ट्रम्प के फैसलों का अमेरिकी और इजराइल की घरेलू राजनीति पर असर पड़ता है। अमेरिकी यहूदी समुदाय, जो पारंपरिक

रूप से लगभग 65% डेमोक्रेटिक है, यू.एस. के भीतर यहूदी-विरोधी में वृद्धि के बावजूद, दक्षिणपंथी समूहों को प्रोत्साहित करने के कारण उसके समर्थन में वृद्धि हुई है। इवांजेलिकल क्रिस्चियन के बीच उनका आधार इजराइल का समर्थन करता है। उनके अभियान में कुछ प्रमुख योगदानकर्ता इजराइल के समर्थक भी हैं।

इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो 9 अप्रैल को होने वाले चुनाव में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और भ्रष्टाचार और दुराचार के लिए अभियोग के खतरे से गुजर रहे है, उन्होंने श्री ट्रम्प पर अपने प्रभाव को इजराइल को भविष्य में मिलने वाले लाभों के रूप में पेश कर रहे हैं। खुद के लिए दक्षिणपंथी समर्थन को मजबूत करने के लिए, उन्होंने सिर्फ घोषणा की कि अगर वह फिर से सत्ता में आते हैं तो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसी यहूदी बस्तियों को इजराइल में मिलाएंगे।

अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत वेस्ट बैंक में इजरायल द्वारा बसाई गई बस्ती अवैध है, लेकिन इजरायल ऐसा नहीं मानता। गौरतलब हो कि इजराइल ने वेस्ट बैंक की बस्तियों में लगभग 400,000 यहूदियों को बसाया है। 200,000 यहूदी पूर्वी जेरूसलम में रहते हैं। वेस्ट बैंक में करीब 25 लाख फिलीस्तीनी रह रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय विरोध का सामना करने के बावजूद, इजराइल और उसके समर्थकों ने, अतीत में भी, अपने उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए वर्तमान समय के सबसे अग्रणी वैश्विक शक्ति का हमेशा ही समर्थन किया है। 2 नवंबर, 1917 को, ब्रिटिश विदेश सचिव, लॉर्ड बालफोर ने घोषणा की थी कि 'उनकी सरकार यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में नेशनल होम बनाने के पक्ष में है।' फलस्तीनी और अरब विरोध के बावजूद, अंतत: 1948 में इजराइल स्टेट की स्थापना हुई।

14 अप्रैल, 2004 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन को पत्र भेज कर कहा था कि "नई वास्तविकताओं के आधार में, पहले से मौजूद प्रमुख इजराइली जनसंख्या केंद्रों सहित, यह उम्मीद करना अवास्तविक है कि अंतिम स्थिति वार्ता का परिणाम 1949 की युद्धविराम पंक्तियों के लिए एक पूर्ण वापसी होगी"(1967 के संघर्ष से पहले की स्थिति)। इजराइल द्वारा वेस्ट बैंक में इजराइल/यहूदी बस्तियों की वैधता स्थापित करने की प्रक्रिया की शुरुआत के रूप में कई लोगों द्वारा इसकी व्याख्या की गई है और एक पूर्ण संप्रभु और सन्निहित फिलिस्तीनी राज्य की व्यवहार्यता को दरकिनार किया गया है।

निश्चित रूप से श्री नेतन्याहू की नवीनतम घोषणा इसे और आगे ले जाएगी। इजराइल के राजनीतिक प्रवचन में, जो समय के साथ सही हो गया है, कई अब दो देशों के समाधान की संभावना पर सवाल उठाते हैं। इजराइल के लिए बाधा यह है कि एक लोकतांत्रिक और यहूदी देश का इसका लक्ष्य अरब और यहूदी आबादी के बराबर अनुपात के साथ 'एक-देश समाधान' में हासिल करना मुश्किल होगा।

गोलन हाइट्स पर श्री ट्रम्प की घोषणा इसे एक कदम और आगे बढ़ाती है। सीरियाई गोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस का हिस्सा था और इसलिए तकनीकी रूप से बालफोर घोषणा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया। श्री ट्रम्प अब 1940 के दशक में फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र के विभाजन की योजना से परे, बालफोर से परे और 1948-49 के अरब-इजरायल संघर्ष के नतीजे से परे, इजराइली संप्रभुता को मान्यता देने की मांग कर रहे हैं।

25 मार्च के अपनी उद्घोषणा में, जिसे इजरायल के प्रधानमंत्री की उपस्थिति में जारी किया गया था, श्री ट्रम्प ने इजराइल के सुरक्षा हितों और क्षेत्रीय खतरों का हवाला दिया है। सीरिया की वर्तमान स्थिति से हम सभी परिचित है। जहाँ एक तरफ अमेरिका अपनी सैन्य उपस्थिति को कम करना चाहता है तो वही दूसरी तरफ रूस और ईरान ने अपनी उपस्थिति और प्रभाव को काफी बढ़ाया है।

इजराइल सीरिया में गोलन से परे ईरानी उपस्थिति और लेबनान की ओर हिजबुल्लाह के बारे में चिंतित है। इसने बार-बार ईरानी ठिकानों और आपूर्ति को निशाना बनाया है, जिसमें हिज्बुल्लाह भी शामिल है। श्री ट्रम्प की घोषणा के बाद, यूएस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने ट्वीट किया कि गोलन हाइट्स में "सीरियाई या ईरानी शासन को नियंत्रण करने की अनुमति देना असद के अत्याचारों और उस क्षेत्र में ईरान की अस्थिरता पर से आँखें बंद कर लेने के सामन होगा।"

उत्साहहीन वैश्विक प्रतिक्रिया

नई अमेरिकी स्थिति को किसी अन्य देश से समर्थन नहीं मिला है, जिसमें उसके यूरोपीय सहयोगी भी शामिल हैं। अगर हम भारत की बात करते है तो इसके हित सीधे तौर पर शामिल नहीं हैं। भारत का इजराइल के साथ संबंध मजबूत और लगातर बढ़ रहा है और इसने सीरिया के साथ भी अपने संबंधों को बनाए रखा है। गोलन हाइट्स पर भारतीय सैनिक संयुक्त राष्ट्र की शांति स्थापना का हिस्सा रहे हैं। हालाँकि, श्री ट्रम्प का कदम पश्चिम एशियाई क्षेत्र में भारत के लिए दीर्घकालिक प्रभाव के साथ भू-राजनीति को बदलने का संकेत देता है। यह एकतरफा वाद का भी दावा करता है, एक नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए चुनौती भी है।

गोलन हाइट्स

चर्चा में क्यों?

- अमेरिका ने गोलन पहाड़ियों को इजराइल के इलाके के रूप में मान्यता दे दी है।
- डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पर लिखा, "52 सालों के बाद अब समय आ गया है जब अमेरिका गोलन पहाड़ी क्षेत्र पर इजरायल के प्रभुत्व को मान्यता दे, जोकि इजराइल और क्षेत्र की स्थिरता के लिए रणनीतिक और सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है।"
- सीरिया के साथ युद्ध के दौरान 1967 में इजराइल ने गोलन पहाड़ियों को अपने कब्जे में ले लिया था। तभी से दोनों देशों के बीच इस इलाके को लेकर विवाद चला आ रहा है।
- इजराइल ने 1981 में इस इलाके पर अपना दावा बताते हुए गोलन पहाड़ियों में अपना प्रशासन और कानून लागू किया था, लेकिन दुनियाभर के देशों ने इसे मान्यता नहीं दी थी।
- पहली बार फरवरी 2017 में व्हाइट हाउस में हुई ट्रम्प के साथ बैठक में इस मांग को उठाया गया था।

क्या है?

- गोलन हाइट्स दक्षिणी-पश्चिमी सीरिया में स्थित एक पहाड़ी इलाका है। ये इलाका राजनीतिक और रणनीतिक रूप से खासा अहम है।
- गोलन हाइट्स मध्य पूर्व के लेवेंत में एक विवादित क्षेत्र है, यह लगभग 1,800 वर्ग किलोमीटर (690 वर्ग मील) फैला हुआ है।
- इसके पूर्व में सीरिया, पश्चिम में इजराइल, उत्तर में लेबनान और दक्षिण में जॉर्डन है।
- इजराइल के मुताबिक, उसने 1,150 वर्ग किलोमीटर (440 वर्ग मील) पर कब्जा कर लिया है। सीरिया के मुताबिक गोलान हाइट्स 1,860 वर्ग किलोमीटर (718 वर्ग मील) का क्षेत्र है, जिसमें से 1,500 वर्ग किमी (580 वर्ग मील) इजराइल द्वारा कब्जा कर लिया गया है।
- सीआईए के अनुसार, इजराइल में यह क्षेत्र 1,300 वर्ग किलोमीटर (500 वर्ग मील) है।

पृष्ठभूमि:-

- इजराइल ने 1967 में सीरिया के साथ छह दिन के युद्ध के बाद गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया था।
- उस वक्त इलाके में रहने वाले ज्यादातर सीरियाई अरब लोग अपना-अपना घर छोड़कर चले गए थे।
- सीरिया ने 1973 में हुए मध्य पूर्व युद्ध के दौरान गोलान हाइट्स को दोबारा हासिल करने की कोशिश की।लेकिन युद्ध में इजराइल को भारी नुकसान पहुंचाने के बावजूद सीरिया ऐसा करने में नाकाम रहा।
- 1974 में दोनों देशों ने इलाके में युद्ध विराम लागू कर दिया. संयुक्त राष्ट्र की सेना 1974 से युद्धविराम रेखा पर तैनात है।
- 1981 में इजराइल ने गोलन हाइट्स को अपने क्षेत्र में मिलाने की एकतरफा घोषणा कर दी। लेकिन इजराइल के इस कदम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता नहीं दी गई।
- गोलन हाइट्स पर यहूदियों की 30 से ज्यादा बस्तियां हैं, जिनमें करीब 20,000 लोग रहते हैं. इलाके में 20,000 सीरियाई लोग भी रहते हैं।

रणनीतिक महत्व:-

- गोलान हाइट्स की चोटी से दक्षिणी सीरिया और सीरिया की राजधानी दमिश्क साफ नजर आते हैं। ये दोनों इलाके यहां से करीब 60 किलोमीटर ही दूर है।
- 1948 से 1967 तक जब गोलान हाइट्स पर इसराइल का कब्जा था, तब सीरिया ने भी उत्तरी इजराइल में अपनी सैन्य हलचल बढ़ा दी थी।
- गोलन हाइट्स से इजराइल को ये फायदा मिलता है कि वो यहां से सीरिया की गतिविधियों पर बराबर नजर रख सकता है।
- ये पहाड़ी इलाका सीरिया से इजराइल की सुरक्षा के लिए ढाल का काम भी करता है।
- गोलन हाइट्स इजराइल के लिए दूसरी कई वजहों से भी अहम है। गोलन इस सूखे इलाके के पानी का मुख्य स्रोत है।
- गोलन में होने वाली बारिश का पानी जॉर्डन की नदी में जाकर मिल जाता है। ये इजराइल की एक तिहाई पानी की जरूरत पूरा करता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'गोलन हाइट्स' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
   1. यह इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवादित क्षेत्र है।
   2. यह इजराइल और लेबनान के मध्य विवादित क्षेत्र है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1 (b) केवल 2
   (c) 1 और 2 दोनों (d) न तो 1 और न ही 2

1. **Consider the following statements regarding Golan Heights-**
   1. It is a disputed area between Israel and Palestine.
   2. It is a disputed area between Israel and Lebanon.

   Which of the above statement is/are correct?
   (a) Only 1 (b) Only 2
   (c) Both 1 and 2 (d) Neither 1, Nor 2

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: हाल ही में चर्चा में रहे 'गोलन हाइट्स' को अमेरिका द्वारा इजराइल के पक्ष में मान्यता देना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करेगा? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. How will the U.S. recognition of 'Golan Heights' in the favour of Israel affect international politics? Discuss.

(250 Words)

नोट : 8 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(a) होगा।

GS World
Committed To Excellence